लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-30 जून 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-20

"ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है।

: स्वामी दयानंद

महानगरीय विकास प्राधिकरण बनने से बढ़लेगी पंचकूला की तस्वीर 3

मिट्टी परीक्षण योजना : कृषि क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम 4

वन्य प्राणियों के संरक्षण की जरुरत 7

करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

विशेष प्रतिनिधि

'सबका साथ, सबका विकास' की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रदेश को करीब 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली, सड़क संबंधित व अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। 21 मार्च, 2021 को भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को 1,411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफ़ा दिया था।

पंचकूला

पंचकूला को लगभग 160 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में खतिया बड़ीशेर से भोज कोटि सड़क पर निर्मित एच.एल. पुल और सेक्टर-2, पंचकूला में निर्मित कल्याण भवन शामिल है। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला के परिसर में एमसीएच और सर्विस ब्लॉक का निर्माण, सिविल अस्पताल, सेक्टर-6 के परिसर में मलेरिया कार्यालय भवन का निर्माण और नारायणगढ़-रायपुर रानी सड़क का चौड़ाकरण का कार्य शामिल है।

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र वासियों को करीब 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया गया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सरस्वती के पुराने पुल का पुनर्निर्माण, लघु सचिवालय के नए प्रशासनिक ब्लॉक, पिहोवा तथा गांव मल्लिकपुर में 33 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन शामिल है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें करनाल-रंबा-इंद्री-लाडवा सड़क को फोरलेन बनाना और शाहाबाद-बराड़ा रोड पर बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से गेट का निर्माण कार्य शामिल है।

करनाल

करनाल जिले के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें करनाल में 33 केवी का सब स्टेशन व नगर निगम की दो जेटिंग मशीन शामिल हैं। शिलान्यास परियोजनाओं में गांव चकदा में 33 केवी का सब स्टेशन व गांव बांसा में बनने वाले 33 केवी का सब स्टेशन तथा आवर्धन नहर का नवीनीकरण कार्य शामिल है।

जींद

जींद जिलावासियों को लगभग 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया गया। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन और सफीदों उपमंडल के हाट गांव में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन,नरवाना के तकनीकी कॉलेज में बनने वाले छात्रवास, सलेहडा गांव में 33 केवी क्षमता का सब स्टेशन और पेगां गांव में बनने वाले आईटीआई भवन का शिलान्यास शामिल हैं।

सोनीपत

सोनीपत जिलावासियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं दी गई। गांव गामड़ी और अनायत में दो उप स्वास्थ्य केंद्र, गांव जाखोली में दो आवासीय क्वार्टर सहित पीएचसी, आरजीईसी में फायर स्टेशन बिल्डिंग, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खानपुर कलां में सीएसआर के तहत पीएसए ऑक्सीजन प्लांट (1000 एलपीएम) का उद्घाटन किया गया।

हिसार

हिसार जिलावासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें हिसार-सदलपुर रेलवे लाइन पर एल/सी नंबर 4-ए पर बनाए गए दो-लेन आरओबी, गांव नियाना में उप स्वास्थ्य केंद्र, गांव सिसखाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बालसमंद में बना नया बस स्टैंड शामिल है ।

रोहतक

रोहतक वासियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं समर्पित की गई। कलानौर खंड में ब्लॉक कार्यालय भवन, कत्थारा-खिड़वाली-ब्राह्मणवास सांपी मार्ग का अपग्रेडेशन, ड्रेन संख्या 8 से सड़क का अपग्रेडेशन, डीभ से चिमनी सड़क वाया माड़ोधी, बल्लम, काहनौर का अपग्रेडेशन और रोहतक भिवानी मार्ग से बनियानी पटवापुर तक की सड़क का अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास शामिल है।

कैथल

कैथल वासियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं दी गई। कलायत में बने 50 बैड की क्षमता वाले सरकारी अस्पताल, तितरम में बने 33 केवी सब स्टेशन और पाड़ला में निर्मित 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया।

चरखी दादरी

चरखी दादरी के हिस्से में 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आईं। इनमें सांवड़ गांव

(शेष पृष्ठ 2 कालम 2 पर)

पर्यावरण पर विशेष

वृक्षों को पेंशन

हरियाणा में लगभग 2550 वृक्ष 75 बरस के हो गए हैं। अब इन्हें पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने 'प्राण वायु देवता पेंशन योजना' के तहत इन बूढ़े वृक्षों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 2,500 रुपए की राशि अदा करने की घोषणा की है। यह पेंशन योजना 'आक्सी-वन' परियोजना के अंतर्गत है। यह पेंशन राशि शहरी निकायों द्वारा अदा की जाएगी ताकि इन बूढ़े वृक्षों के गिर्द ग्रिल व 'नेमप्लेट' (प्रजाति को दर्शाती हुई) व अन्य आसपास की साफ़ सफ़ाई पर खर्च होगी।

ऑक्सीजन-वन योजना का लक्ष्य आगामी किसी भी आपदा के खिलाफ़ लामबंदी के लिए ऑक्सीजन संकट पूर्णतया दूर करना है। इसके तहत पांच एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की भूमि में आक्सीजन-वन लगेंगे और प्रयोग के तौर पर करनाल की पुरानी बादशाही शहर के साथ-साथ 42 किलोमीटर की लम्बाई में लगभग 80 एकड़ भूमि की निशानदेही की गई है। इस प्रस्ताव आक्सी-वन को अलग-अलग नामों वाले क्षेत्रों में बांटा जाए। इन क्षेत्रों के नाम होंगे 'चित्त वन', 'पाखी वन', 'अंतरिक्ष वन', 'तपोवन', 'आरोग्य वन', 'स्मरण वन' और 'सुगंध सुवास वन'।

इस परियोजना के लिए पहले चरण में पांच करोड़ रुपए रखे गए हैं। 'चित्त-वन' में कचनार, अमलताश, सेमल, सीता-अशोक, जावा, कैसिया, लाल गुलमोहर, स्वर्ण वर्षा और पैल्टन फ्लावर आदि लगाए जाएंगे।

'पाखी वन' में पीपल, बरगद, पिलखन, नीम आदि

स्थानीय लोग योजना में शामिल होंगे: मनोहरलाल

मनोहर लाल ने कहा कि 'प्राणवायु देवता पेंशन' योजना एक अनूठी और भारत में अपनी तरह की पहली योजना होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है, जो पचहत्तर वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल करके इन पेड़ों की देखभाल की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण से हमें शुद्ध प्राण वायु मिलती है। इससे पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। इसके लिए प्रदेश के सभी शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सी वन लगाए जाएंगे।

महत्वपूर्ण जानकारी

- दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ रूस में है उसके बाद कनाडा में उसके बाद ब्राजील में फिर अमेरिका और उसके बाद भारत में 35 अरब पेड़ बचे हैं।
- पेड़ों की कतार धूल-मिट्टी के स्तर को 75 फीसदी तक कम कर देती है और 50 फीसदी तक शोर को कम करती है।
- पेड़ अपनी 10 फीसदी खुराक मिट्टी से और 90 फीसदी खुराक हवा से लेते हैं। एक पेड़ में एक साल में 2,000 लीटर पानी धरती से चूस लेता है।
- दुनिया की 20 फीसदी ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों द्वारा पैदा की जाती हैं। ये जंगल 8 करोड़ 15 लाख एकड़ में फैले हुए हैं।
- पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक जा सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक अंजीर के पेड़ की जड़े 400 फीट नीचे तक पाई गई थी।
- दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के डलारना प्रांत में है, टीजिक्को नाम का यह पेड़ 9,550 साल पुराना है। इसकी लंबाई करीब 13 फीट हैं।

आरोपित होंगे जबकि अंतरिक्ष वन में 'पलाश', ढाक, गूलर, आमला, कृष्ण नील, चम्पा, खैर और बिल्वा आदि के पेड़ लगेंगे।

'आरोग्य वन' में तुलसी, अश्वगंधा, नीम, एलोवेरा, हरड़, बहेड़ा और आंवला आदि जबकि सुगंध वाटिका में चमेली, रात की रानी, सुगंध राज, जैसमीन, परिजात, चम्पा, गुलाब, हनी सकल, पैसीफ्लोरा आदि की बहार होगी। इसी क्रम में 'पंचवटी' के नाम से भी एक क्षेत्र चिह्नित होगा। इसमें पांच तरह के पेड़ होंगे।

- डा चंद्र त्रिखा

संपादकीय

कोरोना और चिकित्सा व्यवस्था

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चुनौती को लेकर हरियाणा सरकार सचेत है और अब इस चुनौती के खिलाफ़ लामबंदी की तैयारी भी आरंभ हो गई है।

इस समय देश में, (वर्ष 2018 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार) कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 25,650 है। सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 15,700 (61.2 प्रतिशत) में केवल एक डॉक्टर उपलब्ध था और 1,974 (7.69 प्रतिशत) स्वास्थ्य केंद्रों पर तो डॉक्टर नहीं थे लेकिन हरियाणा में स्थिति इससे कहीं बेहतर है।

स्वास्थ्य, महिला एवं परिवार कल्याण, जनजातीय विकास, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं पेयजल, आयुष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एड्स कंट्रोल आदि के तहत भी ठोस काम हुए हैं।

आज मिल-जुलकर चुनौती का सामना करना ही सर्वोत्तम विकल्प है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करके ही महामारी से निपटने की रणनीति तैयारी की जानी है।

प्रत्येक ग्राम स्तर पर पूर्व में गठित ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति इस कठिन दौर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस समिति को तत्काल सक्रिय एवं मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। इस समिति में ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थान, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के साथ जनसंख्या बाहुल्य के अनुरूप पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना है। महिलाओं की भागीदारी इसमें विशेष रूप से सुनिश्चित की गई है। सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास को इसमें मुख्य कार्यकारी भूमिका में रखा गया है। ग्रामीण मोर्चे पर यह समिति कारगर साबित हो सकती है। कोरोना वैक्सीन के प्रति उत्पन्न भ्रांतियों के निवारण में यह समिति विलक्षण भूमिका अदा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस आपदा काल में जांच, निगरानी तथा घर में बंद कोरोना मरीजों तक जरूरी चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में यह समिति मददगार साबित हो सकेगी। पंचायत तर पर गठित 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति' को स्वास्थ्य समन्वय के लिए सरकार प्रति वर्ष अनुदान भी देती है। समन्वय के प्रयोग पहले भी हुए थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया था।

सरकार ने एक प्रयोग और किया। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसने आशा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। साथ ही, आंगनबाड़ी व्यवस्था खड़ी की। यही नहीं, सखी मंडलों का भी गठन किया गया।

बेशक, देश में गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना खड़ी की जा सकती है। साथ ही, स्थानीय निकायों, खासकर ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करके स्थानीय समाज में स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त जागरूकता का संचार किया जा सकता है। हरियाणा इस दिशा में पूरी तरह जागरूक है।

- डा चंद्र त्रिखा

कैशलैस चिकित्सा सुविधा में कोविड शामिल

राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों और उनके आश्रितों को दी जा रही सीमित कैशलैस चिकित्सा सुविधा में अब कोविड-19 बीमारी को भी जोड़ दिया गया है ताकि कोविड-19 से संबंधित मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति की जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, हरियाणा के बोर्ड और निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों, राज्य के सभी मंडल आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी एवं लेखा परीक्षा), सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, राज्य के सभी सरकारी मैडीकल कालेजों के निदेशकों, राज्य के सभी उपायुक्तों, राज्य के सभी सिविल सर्जनों सहित राज्य सरकार के पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक/चिकित्सा अधीक्षकों को जारी किया गया है।

विदेशों में नौकरी कर सकेंगे प्रशिक्षित युवा

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पास आउट होने वाले युवा विदेशों में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे।

युवाओं के कौशल विकास के मकसद से विदेशी एजेंसियों की मदद ली जाएगी।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसी एजेंसियों द्वारा संबंधित देश के मानदंडों के हिसाब से आईटीआई पास आउट युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका टेस्ट लेकर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे टेस्ट पास करने वाले युवा उस देश में जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे और वहां की स्थाई नागरिकता भी हासिल कर सकेंगे।

शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा हर साल एक लाख बच्चों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग में चालक प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग से बात की जाएगी।

प्रदेश में 172 सरकारी और 242 निजी आईटीआई के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020-21 के दौरान सरकारी आईटीआई में 2521 व्यवसाय यूनिट्स में 55,100 सीटों जबकि प्राइवेट आईटीआई में 1436 व्यवसाय यूनिट्स 30,900 से अधिक सीटें दाखिले के लिए जारी की गईं।

इस समय 414 सरकारी व प्राइवेट आईटीआई में 1,24,200 से अधिक सीटें स्वीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं सहित कुल 35 सरकारी आईटीआई स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 13 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 14 का कार्य प्रगति पर है और 8 का कार्य अभी शुरू होना है।

खिलाड़ियों के खातों में पांच लाख रुपए

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कठोर परिश्रम व संघर्ष का सम्मान करने के लिए समय-समय पर नई प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ करती रहती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व तथा खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा टोक्यो ओलम्पिक-2021 में चयनित होने वाले राज्य के पात्र खिलाड़ियों के बैंक खातों में पांच लाख रुपए की 'तैयारी राशि' उपलब्ध करवाई गई है।

खेल विभाग हरियाणा द्वारा ओलम्पिक खेलों में प्रतिभागिता करने के बाद खिलाड़ियों को 15.00 लाख रूपये की ईनाम राशि प्रदान की जाती थी, अब ओलम्पिक खेलों से पहले उपलब्ध करवाई जाने वाली पांच लाख रुपए की यह अतिरिक्त तैयारी राशि राज्य के प्रतिभागी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, डाइट व उनके खेल के विश्वस्तरीय खेल उपकरण प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

टोक्यो ओलम्पिक-2021 के उपरांत इन खेलों में प्रतिभागिता करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए के नकद ईनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी को छह करोड़ रुपए, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को चार करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 2.50 करोड़ रुपए की नकद ईनाम राशि प्रदान की जाएगी।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बंसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

करोड़ों की परियोजनाओं....

पृष्ठ 1 का शेष-

की पीएचसी, गांव गोपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव दगड़ौली में चार एकड़ भूमि में बनाई गई पार्क-सह-व्यायामशाला, गांव कारीआदू में बनी पार्क-सह-व्यायामशाला, गांव कारीधारिणी और पिचौपा कलां में बने दो पार्क-सह- व्यायामशालाओं और गांव बास रानीला में तैयार पार्क-सह- व्यायामशाला और गांव पिचौपा खुर्द, बेरला, मंदौला एवं रावलधी में बनाए गए ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन शामिल है।

भिवानी

भिवानी जिले में करीब नौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें स्वास्थ्य केंद्र, कैरू व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झुप्पा कलां के नव निर्मित भवनों का उद्घाटन शामिल है।

यमुनानगर

यमुनानगर जिलावासियों को नौ करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरस्वती नगर की नई इमारत, जिला परिषद की नवनिर्मित इमारत और इसके साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठलाना में बनाए गए चार कमरों, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलोजी व सामान्य विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्कूल की चारदिवारी व अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है।

पानीपत

पानीपत जिला को पांच करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें कुराना में बने 33 केवी सब-स्टेशन और पानीपत में निर्मित मीडिया सेंटर भवन का उद्घाटन शामिल है।

फरीदाबाद

फरीदाबाद को लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में स्वर्ण जयंती योजना के तहत स्थापित हुए कस्तूरबा सेवा सदन में बने ऑब्जरवेशन होम व सुरक्षा स्थल, सेक्टर-18(ए) में बने नए आईटीआई भवन और सिकरोना गांव में बने आईटीआई भवन का उद्घाटन किया गया।

पलवल

पलवल जिला को करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इन परियोजनाओं में गांव मंडकोला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, गांव खांबी और भिड़ूकी में पीएचसी का निर्माण, गांव अस्वाता में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, हसनपुर का निर्माण, हसनपुर खण्ड में स्पोर्ट्स स्टेडियम, रामगढ़ का निर्माण, गांव मंडकोला में नए पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह एवं अधीनस्थ विश्राम गृह-सह-चतुर्थ श्रेणी आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।

सिरसा

सिरसा जिलावासियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कालांवाली, ममेरा रोड और डबवाली में स्थापित तीन नए 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया।

जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनमें दो बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण और डिंग गांव में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति योजना को मजबूती प्रदान करना, शक्कर, मंदौरी, तरकांवली और माखोसरानी गांवों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनेक सड़कों का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है।

फतेहाबाद

फतेहाबाद की जनता को 80 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसंगा के नया भवन और गांव भिरड़ाना में बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिन परियोजनाओं की आधाशिला रखी गई, उनमें एक दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपर्क सड़क का अपग्रेडेशन कार्य तथा अन्य विकास कार्य शामिल है।

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता पात्र खिलाड़ी नकद पुरस्कार के लिए 25 जुलाई, 2021 तक संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं ।

राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर जितने बेड्स होने चाहिए उतने बेड्स, डॉक्टर व अन्य स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा।

महानगरीय विकास प्राधिकरण बनने से बदलेगी पंचकूला की तस्वीर

संवाद ब्यूरो

पंचकूला की एकीकृत विकास योजना के तेज़ी से क्रियान्वयन और महानगरीय विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) की स्थापना से न केवल पंचकूला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि इससे हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस इंडेक्स में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है। यह प्राधिकरण गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की तर्ज़ पर काम करेगा।

आर्थिक राजधानी बनने का लक्ष्य

वर्ष 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मनोहर लाल की पंचकूला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए पंचकूला इंटिग्रेटिड प्लान तैयार किया गया, जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं निरंतर समीक्षा की गई।

समेकित विकास की भावी योजनाएं

ट्राईसिटी में पंचकूला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। पंचकूला के समग्र विकास और यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने पंचकूला में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग एक तिहाई कम किया है और इन्हें मोहाली और जीरकपुर के बराबर लेकर आई है। ईडीसी और आईडीसी को कम करने के निर्णय से जहां एक ओर पंचकूला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन में अहम लाभ होगा।

चिकित्सा सुविधाएं

पंचकूला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो बड़े अस्पताल सेक्टर-32 और सेक्टर-5 सी में खोले जाएंगे। इसके अलावा, पंचकूला के सेक्टर-3 में 22 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। थापली में वेलनेस सेंटर और पंचकर्मा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। साथ ही, पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

एजुकेशन सिटी

पंचकूला में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में चंडीमंदिर में इसके लिए जगह की तलाश की गई है। इसके अलावा, सेक्टर-23, पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की जा रही है। पंचकूला के सेक्टर-26 में नया संस्कृति मॉडल स्कूल खोला गया और सेक्टर-31 में 1.66 करोड़ की लागत से प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है।

फार्मा उद्योग

पंचकूला हिमाचल और दिल्ली का गेट-वे है, इसलिए पंचकूला में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए पंचकूला को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इस दिशा में बढ़ते हुए बरवाला में दवा उद्योग के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के संपर्क में है। इसके लिए बद्दी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बैठक हो चुकी है और आगे की योजना तैयार की जा चुकी है।

उद्योग

उन्होंने कहा कि बरवाला को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने, पंचकूला आई.टी. पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ संचालित करने जैसे निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पहला फास्ट ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन अक्षय ऊर्जा भवन, पंचकूला में स्थापित किया गया है।

पुरातात्विक संग्रहालय

पंचकूला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा व माता मनसा देवी मंदिर में 54 करोड़ 52 लाख की लागत के विकास कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही, प्रदेश के नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाने के लिए पंचकूला के सेक्टर-5 में एक स्टेट-ऑफ-आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।

मजबूत सड़क तंत्र

सड़क संपर्क को मजबूत करना किसी भी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा है। चूंकि पंचकूला राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हरियाणा सरकार पंचकूला आने वाले यात्रियों को सुगम और सुव्यवस्थित सड़क तंत्र मुहैया करवाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

मोरनी और टिक्करताल आदि पर्यटन स्थलों तक सुगम यातायात के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। पंचकूला-मंधाना-मोरनी-टिक्करताल-रायपुरानी सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है ताकि पर्यटकों का आवागमन सुगम हो सके। साथ ही, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

पिंजौर हवाई पट्टी

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकूला की कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए घग्गर नदी पर पुल भी निर्माणाधीन है। इसके अलावा, पिंजौर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके पूरा होने के बाद जल्द ही लोग एयर टैक्सी सेवा का लाभ उठा सकेंगे, जो हिंडन, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू-मनाली आदि पर्यटन स्थलों के लिए शुरू की जाएगी।

पिंजौर में फिल्म सिटी

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि पिंजौर का विकास पंचकूला की एकीकृत विकास योजना का एक अहम हिस्सा है, इसके लिए वहां फिल्म सिटी बनाने की व्यापक योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा पिंजौर की मंडी को भी पंचकूला के समग्र विकास की योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके फलों एवं सब्ज़ी का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताज़ा फल एवं सब्ज़ियां उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला के सेक्टर-20 में किसान बाज़ार शुरू किया गया है।

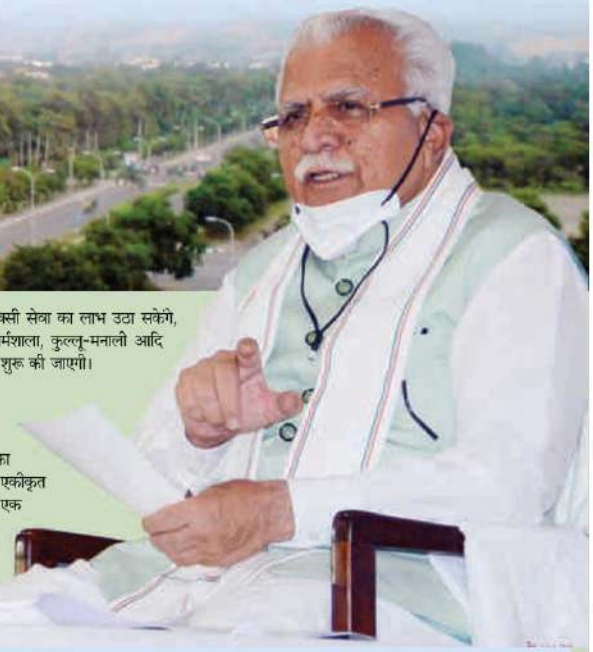

मोरनी हिल्स एडवेंचर स्पॉट

पंचकूला का मोरनी हिल्स क्षेत्र अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि यह शहर आगंतुकों जो पंचकूला से होकर गुजरने वाली ख़ूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए मोरनी में पैराग्लाईडिंग सुविधाओं को विकसित किया है। वहां जल्द ही पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। पैराग्लाइडिंग खेल में काफ़ी जोखिम रहता है इसलिए प्रतिभागियों के बीमा आदि का भी प्रावधान किया जाएगा।

ट्रैकिंग रूट बनाए जाएंगे

पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएंगे, ताकि युवा सायं के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं। होम स्टे/फार्म स्टे पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा, पहाड़ों के लिए टूरिज्म सर्किट रूट, माउंटेन ट्रेल और माउंटेन बाइकिंग के लिए रास्तों की पहचान की गई है।

नक्षत्र, सुगंध वाटिका और राशि वन

पंचकूला के हरे-भरे वातावरण को बढ़ावा देने और इसे संरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पंचकूला से मोरनी रोड के किनारे लगभग 20 एकड़ में नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका और राशि वन स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

नक्षत्र वाटिका में सभी 27 नक्षत्रों से संबंधित पौधे लगाए जाएंगे और इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध होगी। सुगंध वाटिका में सुगंध बिखेरने वाले पौधे लगाए जाएंगे और आस-पास के किसानों को ऐसे पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि सुगंधित तेल बनाने वाले उद्योग में किसान अपनी फसल बेच कर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सकें। इसी प्रकार, राशि वन में सभी 12 राशियों से संबंधित पौधों का रोपण किया जाएगा और इन पौधों और राशियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

डम्पिंग ग्राउंड झुरीवाला में शिफ्ट होगा

सेक्टर-23 के डम्पिंग ग्राउंड में कूड़ा डालना तत्काल बंद करने के साथ-साथ डम्पिंग ग्राउंड को 31 दिसंबर 2021 तक झुरीवाला में पूरी तरह शिफ्ट किया जाएगा। वहां कूड़ा-कचरा पहुंचाना शुरू कर दिया गया है और ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र भी लगाया गया है।

स्कूलों में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकों से 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2021' हेतु ऑनलाइन nationalawardsto-teachers.education.gov.in आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके लिए 20 जून तक पोर्टल/लिंक खोल दिया गया है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मई, 2021 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 79 लाभार्थियों को 51.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है।

मिट्टी परीक्षण योजना : कृषि क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

स्थानीय किसानों में परंपरा रही है कि जो फसल अड़ौसी लगाएगा पड़ौसी भी वही लगाएगा। उसमें आय कम हो या ज्यादा। खेत की मिट्टी व उपलब्ध पानी की गुणवत्ता के आधार पर खेती करने की ओर बहुत कम किसानों ने ध्यान दिया है। परंपरागत खेती से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने पर ध्यान दिया जाए तो सच में खेतों से सोना उगाया जा सकता है।

प्रदेश की प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जांच कर सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने की योजना है ताकि किसान अनावश्यक फर्टीलाइजर के इस्तेमाल से बचें और जमीन में जिसकी आवश्यकता हो वही, पोषक तत्व डालें। इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन के गुणात्मक परिणाम होंगे। कृषि विभाग के अधिकारी वर्ष भर का कैलेण्डर बनाएंगे जिसमें मिट्टी जांच, किसान सभा और प्रदर्शनी आदि के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की तिथियां निर्धारित हों।

75 लाख एकड़ कृषि भूमि की होगी जांच

व्यापक योजना में प्रदेश की 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी जांच का कार्य तीन साल में पूरा किया जाना है। इस जांच के लिए बनाए जाने वाली प्रयोगशालाओं एवं उनके आवश्यक उपकरणों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली गई। प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए होने वाले खर्च के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। योजना के तहत यह जांच हर एकड़ की हर तीन साल में की जाएगी।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें किसान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि अधिकारियों से इस बारे में समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खेती की मिट्टी व पानी का परीक्षण कराने के बाद तय किया जाए कि उस खेत में कौनसी फसल फायदेमंद रहेगी। किसानों से भी आग्रह किया कि वे आंख मूंदकर मेहनत न करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर खेती करें। उन्होंने कृषि भूमि की मिट्टी जांच का काम प्राथमिकता के आधार पर करते हुए चालू वित्त वर्ष में 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर खेत स्वस्थ खेत हो।

सॉयल हेल्थ कार्ड

सॉयल हैल्थ कार्ड में खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों संबंधी जानकारी विस्तार से अंकित होगी। इसमें सॉयल फर्टिलिटी, नाईट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन, जिंक और फास्फोरस आदि की मात्रा के संबंध में जानकारी शामिल होंगी। कार्ड बनाने के बाद इसका उपयोग कैसे करना है इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। हैल्थ कार्ड में यह जानकारी भी उपलब्ध रहेगी कि किस एकड़ में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उनकी कमी पूरी करके किसान कौन सी फसल की बिजाई से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। हर गांव का सॉयल फर्टिलिटी मैप भी इस जांच से तैयार होगा जिससे किसानों को परामर्श देने में भी सुविधा रहेगी।

विद्यार्थियों को मिलेगा रोजगार

योजना के तहत सैम्पल एकत्र करने और लैब में जांच के काम में कालेज एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को लगाया जाएगा। इससे विद्यार्थी लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकेंगे। जिस गांव से सैम्पल एकत्र किए जाने हैं, वहां उसी गांव के विद्यार्थियों को यह कार्य दिया जाएगा।

अपने गांव के सैम्पल एकत्र करने और जांच करने के काम को विद्यार्थी न केवल रुचि के साथ करेंगे बल्कि इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस योजना में किसान मित्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसान मित्रों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

पोली हाउस में खेती

कैथल जिला के गांव पाई का युवा किसान प्रदीप ढुल अपने दो एकड़ के खेत में पोली हाउस बनाकर खीरे उगाकर हर वर्ष अपने सभी खर्चे निकल कर दस लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर रहा है। युवा किसान प्रदीप ढुल ने बताया कि सात वर्ष पूर्व वह 12 वी की पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार था उस ने अपने दो एकड़ के खेत में सब्जियां उगाई लेकिन उसे काफी नुकसान हुआ, उसके बाद उसने पोली हाउस लगाकर खेती करनी शुरू की पहले वर्ष तो उसने फूलों की खेती की, लेकिन मंडीकरण न होने के कारण उसे घाटा हुआ लेकिन उसके बाद उसने अपने पोली हाउस में खीरे की खेती करनी शुरू की। युवा किसान प्रदीप ढुल ने बताया कि उस के बड़े भाई नॉर्मल सिंह ने उन्हें पोली हाउस लगाने की प्रेरणा दी थी। उसके पास पोली हाउस से खेती करने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन बैंक से लोन होने पर यह संभव हो पाया, दो एकड़ खेत में पोली हाउस में खीरे की फसल ने उस की जिंदगी बदल दी। उसने अपने खेत ने दस लोगों को रोज़गार देना शुरू किया और साल में खीरे की फसल से वह सभी खर्चे निकल कर दस लाख रुपये बचा लेता है। प्रदीप ढुल ने बेरोजगार युवाओं का आह्वान किया कि वे नौकरी के पीछे भाग कर अपना समय खराब न करें। बेरोज़गार युवक अपने खेत में पोली हाउस लगाकर सब्जियां लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। भूमिहीन बेरोज़गार युवक भी मशरूम और शहद उत्पादन का काम करके अच्छा कमा सकते है।

कैथल जिला कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ कर्मचंद ने बताया कि कृषि विभाग किसानों को पोली हाउस की खेती करने के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है, उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे कम भूमि होने के बावजूद भी पोली हाउस लगा कर खुद अच्छी आय कमा सकते हैं।

सब्ज़ी उत्पादन से ख़ासी आमदनी

सिरसा के माधो सिंघाना गांव के किसान रमनदीप सब्ज़ी उत्पादन व फूलों की खेती करके खासी कमाई कर रहे हैं। इसके लिए वह यू-ट्यूब चैनल को मददगार मानते है, जिसमें खेती की हर बारीकी को दिखाया व समझाया जाता है।

25 वर्षीय युवा किसान रमनदीप ने वर्ष 2013 से 2015 तक जयपुर के हाईकोर्ट में नौकरी भी की। यह नौकरी उन्हें रास नहीं आई और हरियाणा वापिस आकर उन्होंने अपना पुश्तैनी ट्यूबवैल का बिज़नेस संभाला। उनके दादा व पिता गेहूं और चावल की पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन उन्होंने सब्ज़ियों की खेती करनी शुरू की।

उन्होंने एक एकड़ में घीया की फसल उगाई है और एक दिन में पांच क्विंटल घीया सिरसा की मंडी में बेचते है। इसकी कीमत आठ से नौ रुपए प्रति किलो की हिसाब से मिलती है। वह बताते हैं कि चार महीने की फसल में एक एकड़ में सब खर्च को मिलाकर 15,000 रुपए आता है, जबकि 1.20 से 1.30 लाख रुपए प्रतिमाह कमा लेते हैं। वह कहते है कि अच्छा मुनाफ़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी किस्म का बीज को समय पर उगाया जाए। वह कहते हैं कि पारंपरिक खेती के हटकर खेती करने से अच्छी आमदनी होती है, जबकि पहले हमें गेहूं व चावल की खेती करने पर पैसों के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के सहयोग से चार एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाया है और इससे पानी की बचत व पैदावार अच्छी होती है।

नर्सरी से भी आमदनी

उन्होंने बताया कि उनके टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज व गेंदा के पौध की विशेष मांग है। वह बाज़ार से उच्चतम किस्म का बीज खरीदकर लाते हैं और नर्सरी में विशेष देख-रेख के बीच पौध तैयार की जाती हैं। ट्रे पर पौध को तैयार किया जाता है। आधे एकड़ में उन्होंने नर्सरी की हुई है। कई किसान एडवांस में पौध की बुकिंग करवा लेते हैं, उन्हें कीमत कम और अन्य को थोड़ी ज्यादा कीमत लगती है। उन्होंने बताया कि चार कनाल में गेंदे के फूलों की खेती करते हैं और इससे भी अच्छी आमदनी हो जाती है।

-संगीता शर्मा

मांग के अनुसार सब्ज़ियों का उत्पादन

पानीपत के गांव सिवाह के प्रगतिशील किसान रामप्रताप शर्मा लंबे समय से फलों व सब्ज़ियों की अगेती खेती करते आ रहे हैं। वे ज्यादातर उन्हीं फसलों की खेती करते हैं जिन की मांग विदेशों में भी हो।

वे ताइवान से बीज मंगवा कर खरबूजे की खेती कर रहे हैं। शुगर- फ्री खरबूजे की भी खेती करते हैं। फसल में दवाओं का स्प्रे नहीं करते। सोलर लैंप लगाकर पतंगा से फसलों को बचाते हैं। इस प्रोसेस पर करीब 10 हजार रुपए खर्च आता है।

इजरायल की राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के विशेषज्ञों ने उनके फार्म का हाल ही में दौरा कर अध्ययन किया। वो अपने खेतों में शिमला मिर्च, तरबूज ,करेला, स्वीट कॉर्न, टमाटर, घीया, तोरी, खीरा, हरी मिर्च की खेती करते हैं जबकि दूसरे दौर में गोभी, टमाटर ,करेला ,तोरी व स्वीट कॉर्न की अगेती खेती करते हैं।

तरबूज की मांग ज्यादा है। तैयार होने के बाद 100 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। मल्चिंग की खेती में कम से कम एक एकड़ में 70 हजार रुपए खर्च आता है। वह मदर डेयरी, रिलायंस, मेट्रो, बिग बाजार के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को अपना उत्पाद देते हैं। खुद भी मार्केटिंग करते हैं।

-सुरेन्द्र सिंह मलिक

राज्य के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल इकाई स्थापित कर किसानों को इसके प्रति ज़ागरूक किया जाएगा। इससे छोटी से छोटी जोत से भी किसान अधिक आमदनी हासिल कर सकते हैं।

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को टालने का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय कोरोना वैक्सीनेशन है, जिसे लगवा कर अभिभावक स्वयं के साथ-साथ अपने घर में अन्य सदस्यों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं।

कच्चे रजबाहों को पक्का करने की योजना

खेतों को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए 'मिकाडा'

राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और नहरों पर वाटरकोर्स के कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए काडा को मिकाडा के रूप में पुनर्गठित किया है। इस प्राधिकरण के गठन का लक्ष्य उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हर खेत को अधिकतम सिंचाई जल देना है। प्राधिकरण ने सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया है। इसके माध्यम से सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग करना, पानी की बर्बादी को कम करना, फसल के जोखिम को कम करना और खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। प्रदेश में कुल 15,006 रजवाहे हैं, जिनमें से 3,512 कच्चे व 11,494 पक्के रजवाहे हैं। मिकाडा का लक्ष्य रजबाहों से सिंचित भूमि में से 70 प्रतिशत भूमि की सूक्ष्म सिंचाई करना है। यदि इस लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं तो अधिक से अधिक खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे।

इसी उद्देश्य से मिकाडा ने नये रजबाहों के निर्माण और पुराने व जर्जर हो चुके रजबाहों के पुनर्वास के लिए 3 नई परियोजनाएं शुरू की है, जो 31 मार्च, 2025 तक पूरी होंगी। इनमें भाखड़ा कैनाल कमाण्ड फेज-2, डब्ल्यू.जे.सी. कैनाल फेज-4 और जे.एल.एन कैनाल कमाण्ड-2 में 1,546 रजबाहे पक्के किये जाएंगे। इनसे 2 लाख 68 हजार 625 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस कार्य पर 3,700 करोड़ की राशि खर्च होगी। सरकार उन रजबाहों की मैपिंग भी करवा रही है, जो 20 साल से अधिक पुराने हैं। इनको दोबारा पक्का किया जाएगा।

पांच करम के रास्तों को किया जाएगा पक्का

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि बजट सत्र 2019-20 के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले पांच करम के सब कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 1,225 किलोमीटर लंबे 475 कच्चे रास्तों की पहचान की है। इन्हें पक्का करने पर 490 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन रास्तों को अगले चार साल में वर्ष 2023-24 तक पक्का करने का लक्ष्य है।

डीड रजिस्ट्रेशन से 861.09 करोड़ रुपए का राजस्व

हरियाणा में वर्तमान वित्त वर्ष के पहले दो माह अर्थात 1 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान राज्य को डीड रजिस्ट्रेशन से कुल 861.09 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 74,299 डीड रजिस्ट्रेशन से कुल 803.12 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और कुल 57.97 करोड़ रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त हुई।

हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि यह राजस्व कोरोना के संकट काल के दौरान प्राप्त हुआ है। इस संकट की अवधि में भी प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त व तहसीलदारों द्वारा कोविड ड्यूटी में लगातार रहते हुए यह राजस्व एकत्रित करने का काम किया गया है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी सराहनीय है।

दादूपुर में नहीं है गंदे पानी की समस्या

फतेहाबाद का गांव दादूपुर। यहां घरों से निकलने वाला दूषित पानी समस्या नहीं है। इस दूषित पानी को पांच मॉडल तलाबों में सहेजा जाता है। निकासी का गंदा पानी पाइप लाइन के ज़रिये तालाब तक पहुंचता है। तालाब 20-20 फुट गहरे और 70 फुट चौड़े हैं। इस पानी को ट्रीट कर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तालाब में बचे मलबे को खाद के रूप में खेती के लिए प्रयोग किया जाता है।

दादूपुर में करीब 200 घर हैं। गांव को स्वच्छता के लिए जिले के नौ ओडीएफ प्लस गांव में शामिल किया गया है। निवर्तमान सरपंच राधेश्याम बताते हैं कि हर घर में सूखे-गीले कचरे के लिए डस्टबिन रखवाए गए हैं। तालाबों के नजदीक ही चार एकड़ में सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। मनरेगा योजना में पार्क का निर्माण हुआ है। जिस पर 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। गांव के मज़दूरों को सौ दिन रोजगार मिला।

अकसर देखा जाता है जिन क्षेत्रों में सीवरेज नहीं होता। वहां गंदे पानी की निकासी की समस्या रहती है। गांवों में यह समस्या आम है। दादूपुर गांव में योजनाबद्ध तरीके से नालियों के दूषित पानी को इस्तेमाल किया जाता है। सभी तालाब नीचे से कच्चे रखे गए हैं। नीचे से कच्चा रखने का मकसद छह महीने में तालाब की तलहटी में मलबा और गाद जम जाती है। जिसका इस्तेमाल खाद

के रूप में किया जाता है। तीसरे, चौथे और आखिर में पांचवे तालाब में शुद्ध पानी होता है।

ग्रीन पार्क आकर्षण का केंद्र है। यहां ग्रामीणों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। बच्चों का ध्यान बुराइयों की बजाय खेलों में लगे, इसके लिए खेल का मैदान और ओपन जिम बनाई है। पार्क में फव्वारे और सोलर लाइट भी लगी है। पार्क की देखभाल खुद ग्रामीण मिलकर करते हैं। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा पशु अस्पताल को मंजूरी मिल चुकी है। जिस पर 45 लाख खर्च आने का अनुमान है।

मनोज चौहान

इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगी सरकार

हरियाणा सरकार प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व पेट्रोल-डीज़ल वाहनों को इलैक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन करने के लिए एक पोलिसी बनाएगी, इसके लिए वाहन निर्माताओं व उद्योग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में पोलिसी निर्माण को लेकर बातचीत की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, महानिदेशक साकेत कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बने डीजल-पेट्रोल के वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है।

नए इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के अलावा मौजूदा वाहनों का भी समय पूरा होने पर उन्हें इलैक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर के अलावा मुख्य सड़कों पर भी जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

पंचकूला में प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों व बोर्ड-निगमों के अलावा प्राइवेट साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार सभी नए अपार्टमेंट, हाईराइज बिल्डिंग और टेक्नालोजी पार्क में वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बल देगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के डिस्पोजल को लेकर विकसित होने वाली मार्केट को सरकार प्रोत्साहन देगी। इसी तरह क्लीन फ्यूल और अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को प्रोत्साहित दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना समाज के लिए एक बेहतरीन कदम है। योजना के तहत हाल ही में दस शादीशुदा जोड़ों को ढाई-ढाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चैक प्रदान किये गये।

दक्षिणी हरियाणा के लिए हर खेत पानी योजना बनाई है। इसमें किसान की जमीन में लगभग दो कनाल भूमि में टैंक निर्माण पर किसानों को 70 से 85 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है।

अनाथ बच्चों का लालन-पालन करेगी सरकार

हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन-पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। माता-पिता की मृत्यु के बाद जिन बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति बच्चा प्रति मास राज्य सरकार की ओर से परिवार को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष तक की आयु होने तक जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए भी दिए जाएंगे।

जिन बच्चों के देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है उनकी देखभाल 'बाल देखभाल संस्थान' करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थान को आर्थिक सहायता के रूप में 1,500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। यह राशि आवर्ती जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

किशोरियों के लिए संस्थागत देखभाल

जिन लड़कियों ने किशोरावस्था में अपने माता-पिता को खोया है, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत 51,000 रुपए भी इन बालिकाओं के बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि दी जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

परेशानियों के निवारण के लिए कॉल करें

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्र के अंतर्गत 'राज्य बाल कल्याण परिषद का साथ दोस्ती का हाथ, फोन से बात' परियोजना शुरू की है। परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत राज्य भर के बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ-साथ आम जनमानस को चाहे कोरोना महामारी के वर्तमान हालात हो या कोई और से संबंधित संशय को दूर करने के लिए घर बैठे मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी, अंबाल मलिक के मोबाइल नंबर 94161-08132 पर प्रदेश के सभी लोग व बच्चे निशुल्क परामर्श व चर्चा कर सकेंगे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक्सग्रेसिया योजना के दायरे में

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही प्रदेश भर की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को एक्सग्रेसिया के तहत 20 लाख रुपए कवर के दायरे में लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों में प्रदेश के सभी 25 हजार 962 आंगनवाड़ी केंद्रों के 50 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं अपना योगदान दे रही हैं।

आत्मनिर्भर : कोरोना काल में निकाल लिया रोजगार

मनोज चौहान

कोरोना महामारी का पूरा देश डटकर सामना रहा है। मास्क कोरोना की रोकथाम में मजबूत शस्त्र है। यह रोजगार का जरिया भी बना है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को मास्क व पीपीई किट बनाने के काम से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। यमुनानगर जिले का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह अब तक 23 हजार मास्क और चार हजार पीपीई किट बना चुका है। मास्क सरकारी कार्यालयों व स्टॉल लगाकर सस्ते दामों पर समूह के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है।

समूह द्वारा मास्क बनाने का काम पिछले साल लॉकडाउन से जारी है। कोरोना की पहली लहर में यमुनानगर जिले के 620 समूह ने मास्क बनाने का काम किया। जिसमें 3 हजार 247 महिला सदस्य शामिल थीं। सात खंडों के समूह द्वारा मास्क, पीपीई किट, सैनिटाईजर और हैंड वॉश की मार्केटिंग भी की गई।

कालाआम्ब स्थित एक निजी कंपनी और यमुनानगर ग्रामीण आजीविका मिशन कोरोना को हराने में साथ आए। पीपीई किट बनाने का कच्चा माल महिला समूह को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया। एक पीपीई किट की सिलाई पर 50 से 45 रुपए देता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे काम मिला और आत्मनिर्भर बनी। वहीं समूह सदस्यों ने एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर सैनेटाइजर और हैंडवॉश की खंड स्तर पर बिक्री की। पिछले साल लॉकडाऊन में 25 हजार पीपीई कीट और 1500 लीटर सैनेटाइजर और एक हजार लीटर हैंडवॉश समूह द्वारा सेल किया गया।

कोरोना की दूसरी लहर में महिला स्वयं सहायता समूह ने मोर्चा संभाला। समूह द्वारा पीपीई किट और मास्क बनाए जा रहे है। सढ़ौरा खंड के गांव कनीपला में समूहों ने अब तक 4 हजार पीपीई किट बनाई है। पीपीई किट बनाने में गांव की 60 महिलाओं ने काम किया। इसके साथ सरस्वती नगर के लावणा गांव की महिलाओं द्वारा 13 हजार सर्जिकल मास्क को इलास्टिक लगाई और पैकिंग की। मास्क और सैनेटाइजर को सस्ते दामों पर जिले में आम नागरिकों और सरकारी दफ्तरों में सेल किया गया है।

गांव लवाना के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य बलजीत ने बताया कि समूह रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, तो काम-धंधे ठप पड़ गए। ऐसे में ग्रामीण आजीविक मिशन ने जीवन को रोजगार से रोशन कर दिया। उन्होंने बताया कि गांव में 14 स्वयं सहायता समूह हैं। जिसमें 140 महिलाएं काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान 30 हजार मास्क समूह द्वारा बनाए गए और अब 2 हजार पीपीई किट का ऑर्डर मिला है। वैसे समूह की महिलाएं हर महीने सौ-सौ रुपए मिलकर जोड़ती हैं। किसी भी महिला सदस्य को जरूरत पड़ने पर समूह के अकॉउंट से पैसे दिये जाते हैं।

घर बैठे मिल रोजगार

यमुनानगर ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में मिशन की शुरुआत साल 2016-17 में हुई। शुरुआत जगाधरी खंड से हुई थी। इस समय जिले के सभी सात खंडों में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह हैं। 3320 स्वयं सहायता समूह, 176 ग्राम संगठन और पांच कलस्टर लेवल के फैडरेशन हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूह ने पीपीई किट, सैनेटाइजर और हैंडवॉश तथा उसकी मार्केटिंग का काम कर रही है। घर बैठे काम मिलने से ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनीं।

मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरिंद्र कौर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोरोना को हराने में युद्ध स्तर पर लगी हैं। जिले में समूहों द्वारा मास्क व सैनेटाइजर बनाने के साथ-साथ कोविंड 19 के लिए नागरिकों को जागरूक करने का कार्य भी कर रही है।

हर खेत पानी योजना के तहत सरकार किसानों को फव्वारा व ड्रिप सिंचाई पर 85 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है और अब सरकार इन टैंकों पर सोलर पैनल भी लगवा रही है। जिस पर किसानों को 85 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है।

एआईसीटीई द्वारा स्पष्ट किया है कि इग्नू द्वारा प्रदान की गई सभी बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, जिसमें युवा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित थे। उनके प्रमाण-पत्र प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नति के उद्देश्य के लिए वैध माने जाएंगे।

वन्य प्राणियों के संरक्षण की जरूरत

वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए पुरातन काल में हरित प्रदेश हरियाणा के विभिन्न भागों में अनेक सघनवन लहलहाते थे। पुराणों में इस क्षेत्र में काम्यक धन (कसौधा) व्यास वन (सीवन) आदि वनों का उल्लेख मिलता है। इन वनों पर आश्रित जीव जन्तुओं की पोषक, स्वर्णगंगा, मध्यतता, मंदाकिनी अम्बुनंद, जीव कौशिकी वैतरणी आदि नदियों का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्य है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए औद्योगिकरण व जनसंख्या विस्फोट के कारण धीरे-धीरे वनों का सफाया होने लगा। वनों के विनाश का सीधा प्रभाव वनों मे रहने वाली पशु-पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों पर पड़ा। प्रदेश के वनों की शोभा अनेक पशु-पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे सघन वनों का अभाव है जो प्राकृतिक संतुलन के पर्याय वन्य जीव-जंतुओं के संरक्षक हों।

एक समय अंबाला जिले के कलेसर व कलासिया के वनों, मोरनी की पहाड़ियों, अरावली स्थित शाखाओं में शेरों की गर्जना सुनाई देती थी। प्रसिद्ध प्रकृतिविद किन्नीयर के अनुसार हरियाणा में शेरों का लोप 1834 ई. से शुरू हुआ। कलेसर वन कभी बाघों का आश्रय स्थल था। हिसार बीड़ में देखी जाने वाली कृष्ण मृग की लक्खीदार (अनेक मृगों की लंबी कतार) प्रदेश वासियों की स्मृति में आज भी बसी है। गुलदार, चीतल, बघेरा, काकड़, जरखा लकड़बग्घे प्रदेश के वनों की शान थे। नील गाय, कृष्णमृग आदि वन्य प्राणी प्रदेश के विभिन्न वनों में आज भी विचरते देखे जा सकते हैं।

प्रदेश के वनों में अनेक वन्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम और वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने से स्थिति में सुधार हुआ है। अनेक स्थानों पर बनाये गये हिरण अभ्यारण्यों, दुर्लभ जीवों के शिकार पर पूर्णतः रोक व अन्य वन्य प्राणी अभयारण्यों के कारण काफी हद तक प्राणियों का जीवन सुरक्षित हुआ है।

हरियाणा हिरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज भी हिसार व नारनौल के वनों में हिरणों की डारें बेखौफ विचरण करती दिख जाती हैं। कृष्ण मृग जो हरियाणा का राज्य पशु है, उसकी संख्या काफी कम रह गयी है। इनकी संख्या में वृद्धि के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

100 कि.मी. प्रति घंटा से दौड़ने वाले इस सुंदर प्राणी की सुरक्षा के लिए हिसार बीड़ में एक हिरण अभ्यारण्य विकसित किया गया है। पीपली कुरुक्षेत्र के निकट भी एक कृष्ण मृग अभ्यारण बनाया गया है। हिरण की एक प्रजाति, नील गाय अपने नाम के साथ गाय जुड़ा होने के कारण लाभप्रद स्थिति में है। हिसार के विशाल अभ्यारण्य में हिरणों के साथ-साथ नील गाय, चीतल, सांभर आदि पशुओं के दर्शन भी सुलभ हुए हैं।

बंदर और लंगूर हरियाणा के कई क्षेत्रों विशेषकर जीन्द अम्बाला, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ व गुरुग्राम के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। हनुमान जी का अवतार मानने के कारण इन्हें धार्मिक संरक्षण भी प्राप्त है। कैथल कपिलस्थल में इसके नामानुरूप बंदर बहुसंख्या में हैं। देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, हरियाणा के प्रायः सभी क्षेत्रों में मिलता है। राज्य के दक्षिणी जिलों गुरुग्राम महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद में इसकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी काला तीतर है। प्रदेश में पाये जाने वाले अन्य पक्षियों में सारस, बगुला, कौआ, गौरैया, मैना, कबूतर, तोता, गिद्ध, उल्लू, हुदहुद, कठफोड़वा, नीलकंठ, कश्मीरी बटेर, भूरा तीतर, बुलबुल व बाज आदि पक्षी मुख्य हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के जीव विज्ञानी स्व. प्रो. डॉ. योगेन्द्र यादव द्वारा कुछ दशक पूर्व 130 वंशों की 208 प्रजातियों के हरियाणा में पाये जाने वाले पक्षियों की सूची बनायी गयी थी।

प्रदेश में वन्य पशु-पक्षी सम्पदा को संरक्षित करने के लिए पर अनेक उपाय किये जाते रहे हैं। राज्य में विकसित किये गए पशु पक्षी अभ्यारण्य इन्हीं उपायों का प्रतिफल है। हिसार का हिरण अभ्यारण्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत अभ्यारण्य है। इसमें हिरण, नीलगाय, चीतल आदि लगभग 60 प्रजातियों के वन्य जन्तु विचरण करते है। अन्य प्राणी विहारों में नाहड़ का न्यू सिरसा के निकट ओटू पक्षी विहार, भीर विहार, कैथल के निकट छिलछिला वन्य प्राणी विहार पक्षी विहार आदि प्रमुख हैं।

अनेक विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के उपरांत भी हरियाण में पशु-पक्षियों की विलुप्त सम्पदा निःशेष है। आवश्यक है इन वन्य प्राणियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की। यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी को वन्य पशु सम्पदा संरक्षण के पावन कार्य में सहयोग देना होगा ।

सुरेंद्र बांसल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष

योग भगाए रोग

योग व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके साथ में यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन लाता है जो शरीर और मन के लिए बेहतर है। कोरोना काल में योग मददगार साबित हुआ है और योग करके लोगों ने इस बीमारी से निजात पायी है। कोविड रिकवरी के बाद भी कई लोगों को योग से काफ़ी फायदा मिला है।

भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। 21 जून का दिन साल का 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड-19 के मद्देनजर, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा।

हर साल योग दिवस अलग- अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है. इस साल की थीम है - योग के साथ रहें, घर पर रहें। पिछले साल 2020 की थीम था-घर में रहकर योग करें।

2015 में मनाया गया था पहला योग दिवस

11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस माने की घोषणा की थी। जिसके बाद से 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे सबसे लंबा दिन होता है।

योग दिवस के उद्देश्य

योग दिवस पूरे विश्व मे उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों के बारे में शिक्षित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने तथा समाज में शांति और सद्भाव से रहने के प्रति जागरूक करता है। योग सकारात्मक रूप से लोगों की जीवनशैली में बदलाव लाता है और सेहत के स्तर को बढ़ाता है।

योग परिषद के तत्वाधान में प्रसार

योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय बनाने का निर्णय लिया गया हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक समिति का गठन किया है। योग विषय पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसमें शारीरिक शिक्षा की तर्ज पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों विषय सामग्री सम्मिलित होगी ताकि शिक्षा के अलावा छात्रों को योग का प्रशिक्षण भी दिया जा सके।

हरियाणा योग परिषद के तत्वावधान में योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं। प्रदेश में 1000 आयुष योग सहायकों और 22 आयुष योग प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य योग को जमीनी स्तर पर ले जाना और लोगों को योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए योग और व्यायामशालाओं के अलावा ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है।

योग के लाभ

- योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है।
- योग से मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता है।
- इससे आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है।
- योग आत्म-चिकित्सा को बढ़ावा देता है।
- शरीर से विषाक्त पदार्थों और दिमाग से नकारात्मकता को निकालता है।
- योग से आत्म-जागरूकता बढ़ती है।
- योग शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है।
- व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाता है।
- योग करने से एकाग्रता और ध्यान बढ़ता है।
- योग शरीर में तनाव को कम करने में मदद करता है।

केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण नीति में फिर बदलाव किया है। अब राज्यों के बजाय केंद्र सरकार ही भारत में बनने वाली सभी वैक्सीन खरीदेगी। अभी तक राज्यों को 25 प्रतिशत वैक्सीन ओपन मार्केट से लेनी पड़ती थीं। संयोग है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस दिन से ही देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए पहले की तरह कीमत चुकानी होगी। सर्विस चार्ज अधिकतम 150 रुपए प्रति डोज होगा। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

फलदार पौधे न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पोषक एवं खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। किसान फलदार पौधे लगाकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण आज समय की आवश्यकता बन गया है। मानसून के दौरान लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें प्रकृति की ताज़ा हवा मिलती रहे।

जगमग होते म्हारे गांव

मनोज प्रभाकर

क्षेत्रीय विकास के यूं तो अनेक पैमाने होते हैं लेकिन आम बोलचाल में बिजली, पानी और सड़क का जिक्र प्रमुखता से होता रहा है। बात बिजली की करें तो बंसीलाल सरकार के बाद से प्रदेश में विद्युत संकट रहा है। तीन-तीन दिन बिजली के दर्शन नहीं होते थे। दिनों का निर्धारण कर दिया जाता था, उसी के अनुरूप उपभोक्ता अपने कार्यों की योजना बनाते थे। उद्योग धंधे भी उसी पर निर्भर थे। ग्रामीण अंचल में स्थिति यह रहती थी कि हरा चारा काटना हो या बिजली की रई से दूध बिलोना हो वह तीसरे दिन ही संभव हो पाता था। निश्चित समय वह भी नहीं था, आ जाए तब की बात। गर्मी के दिनों में तो सारा दिन-रात लोग हाथों में बीजणा लेकर इधर उधर डोलते रहते थे।

आज स्थिति बदल चुकी है। जैसे-जैसे सुविधाओं में इजाफा हुआ है, अपेक्षाएं बढ़ती चली गई हैं। घंटा दो घंटा बिजली न आए तो लोग व्यवस्था को कोसने लगते हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने क्षेत्र के बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जिसमें बिजली व्यवस्था को प्राथमिकता से लिया गया। एक दो क्षेत्र को सामने नहीं रखा बल्कि 'घर के सारे बल्ब बदल डालने' का लक्ष्य रखा गया जिसका परिणाम आज सबके सामने है। 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत प्रदेश के 75 प्रतिशत गांवों और 10 सम्पूर्ण जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। शेष बचे गांवों को भी इस योजना में जल्द शामिल कर लिया जाएगा।

5287 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने के उद्देश्य से 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना को आगे बढ़ाते हुए 18 मई, 2021 को 17 और नए गांवों को योजना में शामिल किया गया है। जिसमें सोनीपत के 9 गांव रतनगढ़, माजरा, चिटाना, भटाना, गढ़ी हकीकत, करेवड़ी, बड़वासनी, हुल्लाहेड़ी और डेरा, रोहतक के 5 गांव कलिंगा, ककराना, बलियाना, घिलौड़ कलां और घिलौड़ खुर्द, जिला पानीपत का गांव सिमला, झज्जर का गांव माजरा व कैथल का गांव हजवाना शामिल हैं।

'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत अब प्रदेश के 5287 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। वर्तमान में प्रदेश के 75 प्रतिशत गांवों को पूरी तरह जगमग किया जा चुका है तथा इससे प्रदेश के 10 जिले जिनमें पंचकूला, अंबाला, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद शामिल है, जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध है।

'म्हारा गांव जगमग योजना' की शुरूआत एक जुलाई, 2015 को कुरूक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों से बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने, बिजली चोरी रोकने बारे आग्रह किया गया, जिसके फलस्वरूप जिन ग्रामीण फीडरों का लाइन लोस कम होता है उन गांवों को चिन्हित करके 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाती है।

प्रदेश भर में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। शेष बचे गांवों को जल्द ही इस योजना में शामिल कर संपूर्ण प्रदेश को जगमग किया जाएगा। योजना से प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ताओं में बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने, बिजली चोरी रोकने और बिजली निगम के कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यह सब बिजली निगम के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कठिन परिश्रम और ईमानदारी से ही संभव हो पाया है।

बिजली चोरी पर अंकुश, बढ़ा राजस्व

बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा पिछले दिनों 236 टीमें गठित की गई, जिसमें 1700 लोगों को शामिल किया गया और इन टीमों ने उद्योगों, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, मॉल और ईंट-भट्ठों में छापामारी की, जिसके तहत 2600 बिजली के मामले दर्ज किए गए और इसकी वजह से एक महीने में ही बिजली का राजस्व 536 करोड़ रुपए अधिक आया।

ए.टी.एंड सी. लॉसिस को कम से कम स्तर पर लाने के लिए निगम द्वारा विशेष अभियान चलाए गए, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिल जारी करवाना और वर्तमान बिल के साथ-साथ बकाया बिल राशि को भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया, जिसके लिए उपभोक्ताओं में भी बिल भरने के लिए प्रति काफ़ी उत्साह देखा गया। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों से भी बिजली बिल की बकाया राशि भरवाई गई, जिन उपभोक्ताओ ने बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, उनके कनैक्शन काटने का अभियान चलाया गया।

गौरतलब है कि ए.टी.एंड सी. लॉसिस का एक बड़ा कारण बिजली चोरी भी है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर विशेष टीमें गठित करके बिजली चोरी पकड़ने के अभियान चलाए गए, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की गई। निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की तत्परता का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 48,729 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिससे 16,298.67 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया जोकि पिछले वर्ष से लगभग दोगुना है और इसमें से इस वर्ष लगभग 8,280.79 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूल भी हो गई, जिससे निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। बिजली चोरी पर अंकुश लगने से जहां एक ओर बिजली क्षमता में सुधार हुआ है वहीं, दूसरी ओर लाइन लॉस भी कम हुए हैं।

घाटे में इस वर्ष 2.87 प्रतिशत कमी

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल (ए.टी. एंड सी) घाटे में इस वर्ष 2.87 प्रतिशत की कमी आई है। निगम के ए.टी. एंड सी. लॉसिस पिछले वर्ष की तुलना में 16.50 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 13.63 प्रतिशत के स्तर पर आ गए हैं।

ट्यूबवैल कनेक्शन

किसानों द्वारा करीब 50 हजार ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए थे, जिनमें से करीब 35 हजार कनेक्शन दे दिए गए हैं और बाकी भी जल्द दिए जाएंगे। किसानों की एक बड़ी दिक्कत का निवारण करते हुए राज्य सरकार ने ट्यूबवेल की मोटर बनाने वाली 7 कंपनियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिनसे सीधे किसान अपनी मोटर खरीद कर लगा सकते हैं।

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने ट्यूबवैल कनेक्शन के बारे में अधिकारियों को कार्य स्थलों पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जुलाई माह के अंत तक इस कार्य को किया जा सके। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कनिष्ठ अभियांत्रिकी एवं सेवानिवृत्त एसडीओ खंभों के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे।

इन्वर्टर मुक्त करने का लक्ष्य

गुरुग्राम और पंचकूला को निर्बाध बिजली देकर उन्हें इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि बिजली कट के कारणों को एडवांस में दूर किया जाए ताकि बिना बाधा के 24 घंटे बिजली मिल सके। इसमें चाहे खराब ट्रांसफार्मर, बिजली की तारें, पेड़ आदि की समस्याएं हों, उन सभी को पहले से तैयार रखा जाए। इन दो शहरों में ये प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा।

छतों से लाइन हटाने का कार्य जारी

मकानों के ऊपर से और स्कूलों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी हटाने का काम चल रहा है और अगस्त माह तक इन तारों को हटा दिया जाएगा, जिस पर लगभग 96 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे ही, बिजली विभाग ने 8000 बिजली के खंबे खरीदे हैं और यह सभी खंबे लंबी ऊंचाई वाले हैं और जल्द ही खराब खंभों को बदला जाएगा। इसी प्रकार, अगस्त माह तक सभी पुरानी तारों को भी बदलने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

स्मार्ट मीटर से आई पारदर्शिता

विभाग ने 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदे हैं, जिनमें 2 लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर गुडगांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, जल्द ही 20 लाख और स्मार्ट मीटर विभाग खरीदे जाएंगे। इन स्मार्ट मीटर्स में बहुत अधिक पारदर्शिता है। हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो स्थलों पर बिजली के खुले दरबार लगाये जा रहे हैं ताकि बिजली से संबंधित आई शिकायतों का निवारण किया जा सके।

लाभांश

बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 135 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश का चेक प्रदान किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के दास ने बताया कि यह चेक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एनटीपीसी, आईपीजीसीएल और हरियाणा के संयुक्त उद्यम अरावली पॉवर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) में राज्य के इक्विटी योगदान के लिए अंतरिम लाभांश भुगतान का है। राज्य सरकार ने परियोजना में इक्विटी के रूप में 716 करोड़ रुपए का निवेश किया है और लाभांश की राशि के रूप में अब तक 534.25 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं।

ऑनलाइन ठीक करा सकते हैं बिल संबंधी त्रुटि

वैश्विक कोरोना संक्रमण काल में उपभोक्ता घर बैठे अपने बिजली मीटर की रीडिंग संबंधी त्रुटियों को ऑनलाइन माध्यम से ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। अब उपभोक्ताओं को अपने मीटर की बिजली रीडिंग को ठीक करवाने के लिए बिजली कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रीडिंग गलत होने की स्थिति में उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से विभाग की वैबसाईट पर सही मीटर रीडिंग अपलोड करके बिल ठीक करवा सकते हैं।

यह सुविधा घरेलू, गैर-घरेलू और एलटी औद्योगिक श्रेणियों अधिकतम 20 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए है। इसके लिए उपभोक्ता निगमों की वेबसाईट uhbvn.org.in या dhbvn.org.in पर जाकर ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा का उपयोग कर पाएंगे।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com